आईएसआईएस से युद्ध और गठबंधन की दुविधा

*डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी**

युद्धग्रस्त राष्ट्र इराक में आतंकवाद के विरुद्ध विजय प्राप्त करने और लोकतंत्र की बहाली पर अपनी पीठ थपथपाकर वहां से जाने के कुछ ही समय बाद अमरीका के नेतृत्व में सैन्यबल इराक लौट आया है। कुवैत में मुक्ति संघर्ष; मरहूम सद्दाम हुसैन के विरुद्ध युद्ध और तत्पश्चात अलकायदा के खिलाफ़ लड़ाई के बाद यह इराक में अमरीका का चौथा युद्ध होगा। इस नए युद्ध का केन्द्र/लक्ष्य **इस्लामिक स्टेट्स इन इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)** के खतरे का उन्मूलन करना है जिसने इराक और सीरिया के बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लिया है और इसलिए इस युद्ध में सीरिया भी शामिल है।

अमरीका का निर्णय एक लम्बी दुविधा के बाद आया है कि क्या इसे नए सिरे से पश्चिमी एशिया में सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए अथवा उस क्षेत्र के युद्धरत दलों और शासनों को (अपना झगड़ा) स्वयं ही सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए। 15 सितम्बर 2014 को पेरिस में संपन्न बैठक में 50 राष्ट्रों ने आईएसआईएस के विरुद्ध अमरीका के नेतृत्व वाले संगठन में शामिल होने का निर्णय लिया।

अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ा और यह इस अभियान के उद्देश्यों, तौर–तरीकों, परिणाम और निष्पादन के तरीकों के बारे में अंधेरे में हाथ-पांव मार रहा है। फ्रांस इराकी प्रदेशों पर हमले में शामिल होने वाला पहला राष्ट्र बना, किन्तु अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ–साथ इसने भी स्पष्ट किया कि सीरियाई भू भागों को कुचलने का इसका कोई इरादा नहीं है क्योंकि इसे (गठबंधन को) संयुक्त राष्ट्र अथवा सीरियाई सरकार से कोई अधिदेश/समर्थन प्राप्त नहीं है।

फ्रांस द्वारा लिया गया यह निर्णय एक स्पष्ट सन्देश है कि सीरिया में अमरीकी कार्रवाई एकतरफ़ा चाल है और यह संयुक्त राष्ट्र मानदण्डों का घोर उल्लंघन है। यद्यपि अमेरिका दावा करता है कि इसे संयुक्त राष्ट्र से अनुज्ञा/प्राधिकार प्राप्त करने की जरुरत नहीं है क्योंकि इसने खुद इराकी सरकार के आमंत्रण पर ही युद्ध की शुरुआत की थी और फ़्रांस सरकार द्वारा भी इसी प्रकार की दलील दी गई, लेकिन सीरिया के संबंध

में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका की आधिकारिक उद्घोषणा अभिपुष्टि करती है कि सीरिया में आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध इसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि सीरिया का अब कोई वैध अस्तित्व नहीं रहा है।

इस क्षेत्र के रणनीतिक खिलाड़ियों में से एक ईरान ने सीरिया में युद्ध को अवैध करार दिया है क्योंकि यह सीरिया की सहमति के बिना लड़ी जा रही है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। इससे पहले, ईरान खुद ही युद्ध में शामिल होने का इच्छुक था और इसने एक से अधिक बार दावा किया था कि क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग अनिवार्य है और आईएसआईएस के विरुद्ध कोई भी युद्ध ईरान के बिना सफल नहीं हो सकता।

सीरियाई राष्ट्रपति भी गठबंधन में शामिल होने के लिए अत्यधिक आतुर थे लेकिन अमेरिका ने अरब के अन्य सहयोगियों के अत्यधिक दबाव के चलते यह आरोप लगाते हुए इंकार कर दिया कि ईरान और सीरिया दोनों ही इराक और सीरिया में अपनी अलगाववादी और विशिष्ट नीतियों के कारण समस्याओं की वजह हैं। ईरान और सीरिया को गठबंधन से बाहर रखने का अमेरिका का निर्णय यह जताने की इसकी प्रतिबद्धता के कारण लिया गया निर्णय प्रतीत होता है कि यह सुन्नी बहुल आईएसआईएस के खिलाफ़ कोई शिया गठबंधन नहीं है, जिससे इसके खाड़ी के सहयोगी नाराज हो सकते थे।

सऊदी अरब के नेतृत्व में खाड़ी के राष्ट्रों ने गठबंधन में शामिल होने की अमेरिका की इच्छा पर मुहर लगाने में तनिक भी देरी नहीं की क्योंकि उन्होंने इसे आईएसआईएस का मुकाबला करने की आड़ में राष्ट्रपति असद को बेदखल करने के लिए खुदा की फ़जल से मिले मौके के रूप में माना। गठबंधन में शामिल होने की खाड़ी देशों की इच्छा को आईएसआईएस को हराने के किसी नेक इरादे से ज्यादा असद को हटाने की रणनीतिक लालसा के रूप में देखे जाने की जरुरत है। एक अरबी टीकाकार ने बहुत ही सही तरीके से लिखा है कि अमेरिका ने गठबंधन नहीं बनाया बल्कि यह मिस्टर असद के खिलाफ़ अरब गठबंधन में शामिल भर हुआ है। खाड़ी के राष्ट्रों के साथ गठबंधन इस युद्ध को तब और अधिक विरोधाभासी बना देता है जब अमेरिकी सेनाओं की संयुक्त कमान की अध्यक्ष ने पाया कि कुछ अरब राष्ट्र मिस्टर असद को बेदखल करने में स्वतंत्र सीरियाई सेना की नाकामी के कारण आईएसआईएस को धन मुहैया करा रहे हैं।

यद्यपि तुर्की गठबंधन में शामिल होने के अमेरिकी दबाव के सामने झुक गया है, लेकिन इसकी रणनीति इसकी अपनी आंतरिक राजनीतिक परिवर्तनशीलता से कहीं ज्यादा संचालित मालूम होती है। तुर्की ने अपने राजनयिकों के बंधक संकट के कारण लम्बी उधेड़बुन के बाद गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया। तुर्की में बड़ी संख्या में अलावी (असद समर्थक समुदाय) की उपस्थिति और तुर्की-सीरिया सीमा पर बड़ी संख्या में कुर्द जनसंख्या की उपस्थति ने तुर्की को संकट में डाल दिया है।

तुर्की इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि तुर्की-सीरिया सीमा पर कोबानी-ए–कुर्दिश केंद्र में आईएसआईएस का कमजोर होना कुर्द की स्वतंत्र होने की महत्वकांक्षा को मजबूती प्रदान करेगा जिससे तुर्की

में अस्थिरता फैलेगी। तुर्की ने कोबानी में आईएसआईएस के विरुद्ध कुर्दों के संघर्ष को (कुछ) शर्तों पर समर्थन दिया है और उनसे सीरियाई शासन से राजनीतिक दूरी बनाये रखने के लिए कहा है जो अपने रणनीतिक फायदे के लिए उनका (कुर्दों का) इस्तेमाल कर रहे हैं।

तुर्की ने अमेरिका से सीरिया–तुर्की सीमा (कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के गहरे प्रभाव वाला एक कुर्द केंद्र) पर उड़ान-रहित क्षेत्र बनाने के लिए कहा है, लेकिन अमेरिका ने अब तक इसे नहीं माना है। अधिकांश खाड़ी राष्ट्रों की तरह तुर्की का निर्णय भी मिस्टर असद को बेदखल करने की इसकी चिरकालिक इच्छा से उपजा है और यह इस क्षेत्र में अपने अन्य रणनीतिक उदेश्यों की प्राप्ति के लिए बहाने के रूप में आईएसआईएस के विरुद्ध युद्ध का उपयोग करना चाहेगा। कुर्द समूह चाहता है कि तुर्की सरकार कोबानी का आईएसआईएस से बचाव करे जबकि तुर्की ने कोबानी से लगी अपने सीमा को इसलिए बंद किया हुआ है कि वह आईएसआईएस के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होने के लिए तुर्की कुर्दों को चोरी चुपके जाने से रोक सके। तुर्की ने आईएसआईएस और कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को एक दूसरे की प्रतिमूर्ति करार दिया है क्योंकि दोनों ही इसकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं।

यह केवल असद और आईएसआईएस के बीच की दुविधा भर नहीं है, जिसने गठबंधन को संशय में डाला हुआ है, बल्कि धरती पर पांव ज़माने की इच्छा ने गठबंधन को राजनीति-रहित इकाई बनाकर छोड़ दिया है। अमेरिका ने पहले ही इस बात से इनकार किया है कि इराक अथवा सीरया में सैनिक भेजने का इसका कोई इरादा है, लेकिन यह चाहता है कि जमीनी लड़ाई में अरब राष्ट्र भाग लें। अमेरिकी संयुक्त सेना के प्रमुख ने स्वयं ही माना है कि हवाई हमले गठबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार, आईएसआईएस सदस्यों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल कार्य है क्योंकि वे बड़ी संख्या में असैनिक जनता के बीच जा मिले हैं जिससे युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर अतिरिक्त क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है।

निष्कर्षत: यह एक ऐसा मुद्दा होगा जो अलकायदा के विरूद्ध युद्ध की तरह का नहीं होगा क्योंकि आईएसआईएस अलकायदा से चार गुना बड़ा है और बिना किसी स्पष्ट रुपरेखा (ब्लू प्रिंट) वाला एक धनवान समूह है। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन आईएसआईएस के कमजोर होने का फायदा असद को कमजोर करने में उठा सकता है, जबकि असद आईएसआईएस के नाम पर उदारवादी ताकतों को निशाना बना सकते हैं। कोई भी यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि गठबंधन के वापस जाने और आईएसआईएस के सफाए के बाद खाली हुए सत्तारूपी शून्य को कौन भरेगा। बेशक अमेरिका चाहेगा कि उदारवादी ही सत्ता में आएं लेकिन वे इतने शक्तिशाली भी नहीं हैं, क्योंकि उन पर सीरिया में शासन तथा अतिवादी दोनों पक्षों से हमले हो रहे हैं। यह देखने की भी जरुरत होगी कि क्या यह आईएसआईएस के आतंक के विरुद्ध युद्ध होगा अथवा मिस्टर असद के दमन के विरूद्ध।

*डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।